Buying the Stake of Nauru Government in Paradeep Phosphates

2770. SHRI B. K. HARIPRASAD : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India bought 49 per cent stake of Nauru Government Paradeep Phosphates;

(b) whether the Ministry of Finance had expressed reservations on this buyout proposal vigorously, mooted by the Ministry of External Affairs; and

(c) whether it is a fact that Government sacrificed our commercial interests by doling out Rs. 200000 crores to Nauru already 20 times richer than India just to acquire a vain glory on the diplomatic front ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir, the Ministry of Finance was closely involved with the examination of the proposal and concurred with the recommendation which was approved by the Cabinet.

(c) Paradeep Phosphates Ltd., (PPL), set up as an Indo-Nauru Joint venture in 1982, had made no profits since its inception. Nauru had been pressing the Government of India for some years for selling its equity and withdrawing from PPL. Nauru eventually signed a memorandum of understanding with the ESSAR Group for disposing off its share in PPL for Australian Dollars 63.8 million (Rs. 135.745 crores approximately) and requested the Government of India's approval for the sale. Since the fixed assets of PPL were considerably in excess of the proposed sale price to the ESSAR Group, the Government of India decided to purchase the shares itself at the same price as had been offered by ESSAR. The purchase was accordingly entered into in the best commercial interests of the Government of India.

रूस द्वारा पाकिस्तान को परमाणु सहायता

2771. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1993 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "रशिया, पाक जोइन हैन्ड्स ओन एन प्लांट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि रूस ने पाकिस्तान की परमाणु परियोजनाओं के संबंध में सहयोग देने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान द्वारा इन परियोजनाओं का परमाणु शस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है जिसके कारण भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में रूस के साथ बातचीत की है, और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में रूस की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां । सरकार को 8 अप्रैल, 1993 के संयुक्त प्रेस वक्तव्य की जानकारी है जो रूस के विदेश मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा के बाद जारी किया गया था । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ समुचित अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षोपायों के अनुसार नाभिकीय शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोग में सहयोग का प्रावधान है ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार रूस ने उपरोक्त संयुक्त वक्तव्य के पालन में नाभिकीय परियोजनाओं के संबंध में पाकिस्तान के साथ कोई सौदा तय नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) रूस की सरकार को पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम, जिसमें उसके नाभिकीय शस्त्र बनाने के चोरी-छिपे किए गए प्रयास शामिल हैं, के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण की जानकारी है । सरकार के विचारों से रूस की सरकार को आवधिक द्विपक्षीय विचार विनिमय के दौरान अवगत कराया जाता रहा है ।

पाकिस्तान के प्रशिक्षण शिविरों के स्थान का बदला जाना

2772. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने भारत में तोड़-फोड़ करने की गतिविधियां जारी रखने के लिए विघटनकारी तत्वों को प्रशिक्षण देने के शिविर स्थलों का स्थान बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो नवीनतम जानकारी के अनुसार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर अब ऐसे प्रशिक्षण शिविर स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन शिविरों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ को सूचित किया है; और